

बजट अनुमान 2004-2005

वर्ष 2004-2005 के बजट अनुमान संशोधित अनुमानों की तुलना में राष्ट्रीय लघु बचत निधि को देनदेरियों की वापसी-अदायगी को छोड़कर 50,177 करोड़ रुपए की निवल वृद्धि दिखाते हैं। जबकि आयोजना-भिन्न व्यय में वृद्धि 26,094 करोड़ रुपए है, आयोजना व्यय के अधीन 24,083 करोड़ रुपए की वृद्धि है जिसमें से 15,039 करोड़ रुपए केन्द्रीय आयोजना पर व्यय के लिए हैं और 9,044 करोड़ रुपए राज्य और संघ राज्य क्षेत्र की आयोजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता पर व्यय के लिए है। आयोजना-भिन्न और आयोजना अनुमानों में मुख्य मदों की घट-बढ़ को नीचे सारणी में दिया गया है:-

(करोड़ रुपए)

	संशोधित 2003-04	बजट 2004-05	घट-बढ़
आयोजना-भिन्न			
1. ब्याज संदाय	120475	129500	(+) 9025
2. पूर्व अदायगी प्रीमियम	4080	...	(-) 4080
3. रक्षा	60300	77000	(+) 16700
4. स्टाफ सब्सिडी	25200	25800	(+) 600
5. उर्वरक सब्सिडी	11797	12662	(+) 865
6. पेट्रोलियम सब्सिडी	6573	3559	(-) 3014
7. राज्य सरकारों को अनुदान/ऋण	15017	18821	(+) 3804
8. कृषि और संबद्ध सेवाएं	1081	1784	(+) 703
9. पुलिस	8331	9940	(+) 1609
10. चुनाव	461	1162	(+) 701
11. अन्य आयोजना-भिन्न व्यय	52830	52011	(-) 819
जोड़ (आयोजना-भिन्न) व्यय	306145	332239	(+) 26094
आयोजना			
1. केन्द्रीय आयोजना	72847	87886	(+) 15039
2. राज्य और संघ राज्य क्षेत्र की आयोजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता	48660	57704	(+) 9044
जोड़ (आयोजना) व्यय	121507	145590	(+) 24083

आयोजना-भिन्न

- वृद्धि का कारण सरकारी व्यय को वित्तपोषित करने के लिए ऋण संसाधनों पर लगातार निर्भर होना रहा है। इसमें मार्किट स्थिरीकरण स्कीम के अन्तर्गत उधारों पर प्रावधान भी शामिल हैं।
- इसमें कोई पूर्व भुगतान प्रीमियम विहित नहीं है।
- बढ़ा हुआ प्रावधान वेतन और भत्तों पर अतिरिक्त व्यय को पूरा करने और संविदागत देयताओं को पूरा करने और रक्षा बलों के आधुनिकीकरण के लिए है।
- खाद्यान्नों के वृद्धित उठान के कारण है।
- यह वृद्धि यूरिया और नियंत्रण-मुक्त उर्वरकों की आवश्यकता में प्रत्याशित वृद्धि के कारण है।
- यह कमी एक निश्चित समयावधि के भीतर पेट्रोलियम सब्सिडी को चरण बद्ध तरीके से समाप्त करने के निर्णय के अनुरूप है।
- यह वृद्धि ग्यारहवें वित्त आयोग की राज्यों को आयोजना-भिन्न अनुदानों की सिफारिशों के आधार पर है।
- यह सहकारी ऋण ढांचे को सुदृढ़ करने के लिए राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) के माध्यम से अनुदानों की व्यवस्था के साथ-साथ सामान्य वृद्धि के कारण है।
- इस वृद्धि में सामान्य अभिवृद्धि के साथ-साथ पुलिस बलों के आधुनिकीकरण हेतु राज्यों को विशेष सहायता शामिल है।
- यह वृद्धि 2004 में आम चुनाव करवाने संबंधी अतिरिक्त व्यय के प्रावधान के कारण है।

आयोजना

- यह वृद्धि अन्य बातों के साथ-साथ राष्ट्रीय साझा न्यूनतम कार्यक्रम के उद्देश्यों को पूरा करने हेतु केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों के लिए नई/पुनर्गठित स्कीमों के लिए, आधारभूत ढांचा विकास के लिए वृद्धित सहायता, सामाजिक क्षेत्र में, विशेष रूप से शिक्षा, परिवार कल्याण, स्वास्थ्य और खास तौर पर विद्युत और सड़कों के वास्तविक आधारभूत ढांचे के लिए 6,000 करोड़ रुपए के एकमुश्त आबंटन के कारण है।
- यह वृद्धि मुख्य रूप से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की योजनाओं के लिए राष्ट्रीय साझा न्यूनतम कार्यक्रम से संबंधित नई/पुनर्गठित स्कीमों की सहायता, सामान्य केन्द्रीय सहायता में वृद्धि और राष्ट्रीय सम विकास योजना के अन्तर्गत वृद्धित प्रावधान हेतु 4,000 करोड़ रुपए के एकमुश्त आबंटन के कारण है।